में भी यह बनता है लेकिन 70 टन प्रति दिन सोडा ऐश की आवश्यकता है जिस का उत्पादन करने में हम दोनों फैक्टरियों ने भी असमर्थता जाहिर की है । इसलिये हम मंत्री महोदय से प्रार्थना करेंगे कि वे बिहार सरकार के आवेदन पत्र पर फिर से विचार कर के उस के इस प्रोजैक्ट के लाइसेंस के वेलीडिटी पीरियड को एक्सटेंड कर दें ताकि बिहार सरकार इस प्रोजैक्ट को बना कर सोडा ऐश का उत्पादन कर सके ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मान्यवर, अगर इस के बारे में नये कारण देते हुए प्रार्थना पत्र आयेगा कि वे किस तरह से इस काम को पूरा कर सकते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है । चार वर्ष तक बिहार सरकार इस प्रोजैक्ट को पूरा नहीं कर पायी जबकि उनके पास लैटर आफ इन्टेन्ट था, लायसेंस था । फिर भी आगे कोई प्रार्थना पत्र आता है तो हम जरूर उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री रामावतार सिंह: बिहार सरकार ने 25-5-77, 28-9-77 और 3-11-77 को इसकी वेलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए प्रार्थना पत्र भेजे थे । अन्त में उसने 3-10-78 को प्रार्थना पत्र भेजा था लेकिन भारत सरकार ने 7-9-78 को उसको जवाब दे दिया । बिहार में इस प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में काफी प्रोग्रेस हो चुकी है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे बिहार सरकार के पत्रों को फिर वे देखें और उन पर विचार करें । भारत सरकार ने इस बीच प्रोफेसर गोपाल त्रिपाठी के नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी भी कंस्टीच्यूट की थी । उस हाई पावर कमेटी ने भी अपनी सिफारिश भारत सरकार को की है कि भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बिहार को इजाजत दे दे; यदि बिहार सरकार इस प्रोजेक्ट को चलाये तो इस कमेटी को कोई एतराज नहीं है । इस के बाद बिहार सरकार ने 13-1-79 को फिर भारत सरकार को पत्र भेजा। इसलिए हम मंत्री महोदय से कहेंगे कि वे इस की जरूरत को देखें । अगर मंत्री महोदय चाहें तो हम बिहार सरकार के सभी पत्रों के नम्बर भी देने को तयार हैं कि वे किस किस नम्बर के हैं और कब तक भारत सरकार को भेजे गये हैं । जो जवाब मंत्री महोदय ने यहां दिया है वह सही नहीं है । इसलिए मैं सप्लीमेंटरी क्वेश्चन द्वारा मंत्री महोदय से फिर प्रार्थना करूंगा कि जो बिहार सरकार ने प्रार्थना पत्र भेजे हैं और हाई पावर कमेटी में जो सिफारिश की है उन सभी को देखते हुए वे इस पर तुरन्त विचार करने का आश्वासन दें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अब तो नई अर्जी आयेगी लाइसेंस के लिये उस पर विचार करेंगे, क्योंकि पिछले तथ्यों पर अब पर विचार करने के बाद हमारी तरफ से इस सम्बन्ध में पुराने लाइसेंस पर काम चलाने की ना हो चुकी है । जहां तक डा० गोपाल त्रिपाठी की कमेटी की रिकमेन्डेशन्स का सवाल है उस पर विचार नहीं रहा है और जब उस पर विचार हो जायगा तो अंतिम निर्णय ले लेंगे ।

श्री नाथू सिंह : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या सरकार के सामने सोडा ऐश आयात करने का विचार है ? यदि हां, तो किन किन देशों से आप आयात कर रहे हैं और कितनी कम्पनियों ने आपसे लाइसेंस मांगा है और कितनी कम्पनियों को आपने लाइसेंस दिया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मान्यवर, आयात का मामला सारा वाणिज्य मंत्रालय से होता है । सोडा ऐश ओ० जी० एल० यानी ओपिन जनरल लाइसेंस में है । किस किस ने उनसे मांगा मैं नहीं जानता, मगर दो बड़े बड़े संगठनों ने—आल इंडिया ग्लास मैनुफैक्चरर्स असोसियेशन और इंडियन सिलिकेट असोसियेशन—इन दोनों ने मांगा था । एक ने बल्गेरिया से मांगा है और एक ने कीनिया से ।

SHRI PURNANARAYAN SINHA: The Minister has said in his statement that 'Fertilizer Corporation of India have, however, been issued an industrial licence for the manufacture of Soda Ash at Haldia, also in Eastern India'. Will the Minister think of establishing a Soda Ash manufacturing factory at Mejenga where there was demand by the people for location of a fertiliser factory in addition to the Namrup factory from where raw materials can be collected?

SHRI H. N. BAHUGUNA: There are no applications. We are talking in the air. If and when applications are received, those will be considered.

Percentage of Coal Mines affected by floods

\+

*322. SHRI SUBHASH AHUJA:
SHRI D. AMAT:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the percentage of the coal mines affected by floods last year to the total number of coal mines; and

(b) the loss suffered by each of these mines as a result there thereof?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पिछले वर्ष की बाढ़ से पूरी तरह या अंशतः प्रभावित कोयला खानों का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

(i) 115 भूमिगत खानों में 49 (42.6%) (प्रभावित खनन जिलों की संख्या 94 है जबकि कुल खनन जिले 348 हैं अतः इनका प्रतिशत 27 है)

(ii) 38 ओपेनकास्ट खानों में से 38—अतः 100% ।

भारत कोकिंग कोल लि०

(i) 90 भूमिगत खानों में से 70 (अतः 77.8%) (बाढ़ग्रस्त खनन जिले 119, कुल खनन जिले 393—अतः 30%)

(ii) 30 में से 29 क्वैरियां प्रभावित हुईं—अतः 96.7% ।

(ख) भूमिगत खानों के विभिन्न खनन जिले और ओपेनकास्ट खानों के कुछ अंश अलग अलग अवधियों तक पानी में डूबे रहे अतः यह पता लगाना कठिन है कि बाढ़ के कारण प्रत्येक खान को अलग अलग कितना नुकसान हुआ । इन दोनों कम्पनियों में बाढ़ से पहले के सामान्य उत्पादन की तुलना में कुल उत्पादन में जो कमी हुई और यह कमी सितम्बर मास में भारत कोकिंग कोल लि० में लगभग 20,000 टन प्रतिदिन और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० में 40,000 टन प्रतिदिन रही । अक्तूबर मास में यह कमी क्रमशः 5,700 टन और 20,000 टन प्रति दिन रही ।

श्री सुभाष आहूजा : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि मैंने अपने प्रश्न के (ख) में यह पूछा है कि इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक खान को कितनी हानि हुई है । मंत्री जी ने उत्पादन का ह्रास तो बताया है, परन्तु कितने रु० की हानि हुई है यह नहीं बताया । तो मैं जानना चाहता हूं कि बाढ़ से प्रभावित कोयला खदानों को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, और क्या पुनः उन कोयला खदानों में उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया गया है, और मशीनों पर कुल कितना व्यय आया है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : मैंने बताया है कि इसका हिसाब हमने रुपये में तो नहीं लगाया है। लेकिन यह सही है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स के उत्पादन में दो लाख टन का नुकसान हुआ है जिसमें से दोनों कम्पनियों में दैनिक उत्पादन में कमी 40,000 टन और 20,000 टन रही है । इस समय जितने खान जिलों में पानी आ गया था खाली कराया जा चुका है । केवल पांच खान जिले ऐसे हैं जिन का पानी खाली कराया जाना अभी बाकी है । हम उम्मीद करते हैं कि इस मार्च महीने में वह भी खाली करवा लिया जाएगा और उन में भी काम शुरू हो जाएगा ।

श्री सुभाष आहूजा : जिन पांच खान जिलों में अभी तक पानी निकाला नहीं जा सका है उसका कारण क्या है ? भविष्य में कोयला खदानों को बाढ़ के खतरे के लिए क्या कोल इंडिया ने कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हां तो उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अब की बार की बाढ़ अभूतपूर्व थी और सरकार सक्रियता के साथ विचार कर रही है कि इस तरह की बाढ़ का भविष्य में कैसे मुकाबला किया जा सकता है ?

श्री सत्यदेव सिंह : पिछले दिनों ट्रेन सर्विसेस और थर्मल पावर जनरेशन दोनों में कोयले की कमी के कारण काम रुक गया था । रेलों को कोयले की सप्लाई और थर्मल पावर स्टेशंज को कोयले की सप्लाई कब तक नियमित रूप से होने लग जाएगी ताकि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और दोनों क्षेत्रों में कार्य ठीक से हो सके ?

श्री जनेश्वर मिश्र : हालांकि यह सवाल मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कोयला विभाग और रेल विभाग कोयले की सप्लाई के बारे में आपस में बातचीत करके जल्दी कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ।

SHRI A. K. ROY: Mr. Speaker, Sir, drowning of mines in rainy season is not a new affair. I would like to know from the hon. Minister whether this is the first time that the mines went under water or in every rainy season a considerable number of mines go under water. This time there was such a big havoc, a lot of mines were drowned and big open cast mines turned into lakes. It is not because of this unprecedented flood, but because of the negligence of the officers to give protection to them and to anticipate that something of that type of flood would come and take precautionary measure against that. So, I would like to know from the Minister whether he would constitute a probe body, a high level probe body, to examine whether this type of drowning of mines is absolutely due to the unprecedented flood or negligence of the officers to give protection against the flood by anticipating it. My question is whether he is ready to constitute a high level probe body to probe into the matter and at the same time, whether this type of floods also occurred in the previous two years or so.

श्री जनेश्वर मिश्र : सरकार की निश्चित राय है कि खानों में अब की बार की बाढ़ कुदरती थी और उस में किसी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है ।

[श्री जनेश्वर मिश्र]

फिर भी माननीय सदस्य अगर निश्चित सुझाव देंगे और बताएंगे कि किसी अधिकारी ने कहीं कोई गलती की है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

SHRI A. K. ROY: Mr. Speaker, S.r, I wanted to know whether in earlier years also this type of floods, may be in small-scale, occurred and the coal fields suffered a loss or not, and whether he has got any data regarding that.

MR SPEAKER: He wants to know whether in earlier years also the:e were some floods and there were damages.

श्री जनेश्वर मिश्र : इस पर आंकड़ा हो जाएगा।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Mr. Speaker, Sir, I would like to know from the hon. Minister the total number of workers who lost their jobs due to the coal mines being affected on account of floods

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): Sir, nobody lost the job because of the floods. They only did not have work for some days and no worker was laid off during the floods

श्री राम दास सिंह : बाढ़ से जो खदानें एफक्ट हुई हैं उनको हम लोगों ने जा कर देखा है। ई०सी एल० की जो खदानें डूब गई हैं वह बिहार और वैस्ट बंगाल के झगड़े के कारण हुआ है। डी०वी०सी० का उनके साथ एक एग्रीमेंट है। बिहार और बंगाल की सरकारों ने तय कर लिया हैं कि जो मथन बांध है वह पांच फुट ऊंचा उठाया जाए। अभी तक तो चालीस परसेंट माइंस ही डूबी थीं लेकिन अगर मथन डम पांच फुट ऊंचा हो गया तो इस साल अगर उतनी बाढ़ आ गई जितनी पिछली बार आई थी तो सैंट परसेंट माइंज डूब जाएगी। डी०वी सी० वाले कहते हैं कि हम क्या करें ? क्या आप का डी वी०सी० पर कोई कंट्रोल है या नहीं ? अगर है तो डी०वी सी०के एक्सपर्ट और कोल इंडिया के एक्सपर्ट दोनों को बिठा करके बांध की ऊंचाई के बारे में क्या आप कोई पहल करेंगे ?

बी०सी०सी०एल० की बाढ़ से माइंस नहीं डूबी हैं। वहां पर बहुत चोर बाजारी हो रही थी। इस वास्ते बी० सी०सी०एल० के मनेजमेंट ने उस कोल माइंज को इसलिये बन्द कर दिया कि वहां पर ओवरलोडिंग नहीं हो रहा था। जैसा मि० राय ने कहा है क्या आप एक कमेटी बनाएंगे जो बी०सी०सी०एल० की इनक्वायरी करे और पता लगाए कि माइंस डूबी थीं या यह मैनमेड चीज थी। जवरीसिडेंटिव बाढ़ की वजह से नहीं डूबी थीं बल्कि उसमें एक षड्यंत्र काम कर रहा था। क्या मंत्री महोदय एक कमेटी गठित कर इसकी जांच करवाएंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं बता चुका हूं कि ईस्टर्न कोल फील्ड्स और बी०सी०सी०एल० दोनों की खानें बाढ़ के कारण ही बन्द हुई थीं और इसके बारे में हमें कोई दूसरी जानकारी नहीं है। इसलिए इनक्वायरी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

SHRI EDUARDO FALEIRO. It is true that the floods did create havoc in the mines, but much of the havoc was not due to floods, but due to disputes between the staff and the officials. as in the case of Dhanbad mines, about which it appeared in the press that the staff refused to operate water control pumps because of a dispute with the Secretary of the Ministry, Mr Varma. Only subsequently the natural floods came, but the responsibility was put on natural floods. Will the Government take steps to see that the security measures are implemented and the staff members are kept satisfied in such a manner that they attend to the work of water control.

SHRI RAM DAS SINGH: I am on a point of order. The Minister has not given a proper reply to my question. I have mentioned that the mines of BCCL which have been affected due to a dispute between the Government of Bihar and the Government of West Bengal. But the Minister had not mentioned anything about it ini his reply. Then, what is the use of putting the question?

MR. SPEAKER: Have you got any answer for that. He says that the watering is due to a dispute between Bihar Government and Bengal Government.

SHRI P. RAMACHANDRAN: It is not because of the dispute between Bihar and West Bengal. If water was not let out in the Damodar valley, the dam would have been burst. That is why it was regulated. The Irrigation Department has got the control over it and they regulate the water in these taps. It is true that for irrigation purpose, both the Governments want a

higher quantum of water to be stored in the reservoir and there is a constant dialogue going on. We are taking into consideration not only irrigation purposes but also the safety of the mines. We are going into all these things.

MR. SPEAKER: Mr. Faleiro, please repeat your question.

SHRI EDUARDO FALEIRO: My question was this. Sometimes the blame is not properly laid, it is always laid on the natural floods, whereas the main cause is the dispute between the staff and the officials, as it was in the case of Dhanbad mines. In the case of Dhanbad there was a dispute between the staff and Shri Varma, Secretary of the Ministry and, in view of the dispute the staff did not operate water-control pumps, the floods that occurred had nothing to do with natural floods. Is this a fact, and what will Government do to prevent such type of incidents in future?

SHRI P. RAMACHANDRAN: So far no such dispute was brought to our notice. In fact, immediately after the floods, in the next 48 hours. I was at the spot and I went round the entire flooded mines and tried to give directions—and because of these steps dewatering was done very quickly and the mines brought to production.

Amendments of Laws for Effective Implementation of New Drug Policy

*305. SHRI RAGHAVJI (on behalf of Dr. Vasant Kumar Pandit): Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state: (a) whether it is necessary to have several amendments to various existing laws to achieve effective implementation of the New Drug Policy of Government;

(b) whether the Law Ministry has studied the implications of the new Drug Policy, if so, their recommendations and suggestions;

(c) whether in many of the old licences issued to Drug Companies, the limitation of licence capacity is not mentioned; requiring amendment to the Industries (Development and Regulation) Act;

(d) whether the small scale drug industries have opposed abolition of sole selling Agencies in the absence of any marketing capacity,

(e) whether legal hurdles have de layed the issue of a new drug and intermediates price control order; and

(f) if so, the steps taken by Government in all the above matters?

THE MINISTER OF PETROLEUM CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Some amendments to existing Statutes would be necessary for the implementation of certain decisions contained in the New Drug Policy.

(b) Law Ministry is being consulted by the Ministries concerned wherever such amendments are considered necessary.

(c) No, Sir. Only in 6 (six) cases, the licences indicated that capacities would be fixed later.

No amendment to the Industries (Development and Regulation) Act is required in this regard.

(d) Representations from a number of Associations of Drug producers were received against the decision to abolish sole selling Agency and these referred to the likely adverse effect of the abolition of sole selling Agency system on the marketing of formulations made by small scale units.

(e) The legal issues have since been sorted out and the Drug (Price Control) Order has been finalised.